

प्रेषक,

जे०पी० जोशी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चमोली।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 15 अक्टूबर, 2015

विषय:- मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में जनपद चमोली में प्रस्तावित 33/11 के०वी० उप संस्थान, थराली की स्थापना हेतु कुल 0.166 है० भूमि उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० (यू०पी०सी०एल०) को सशुल्क पट्टे पर आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं०-6434/छब्बीस-26(2014-2015) दि०-20.07.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, जनपद चमोली की तहसील थराली के अन्तर्गत ग्राम देवराड़ा की सीमान्तर्गत धारी नामक तोक की खतौनी खाता सं०-94 के खसरा सं०-664 मध्ये 0.099 है०, 665 मध्ये 0.020 है०, 666 मध्ये 0.020 है०, 667 मध्ये 0.023 है० तथा खसरा सं०-668 मध्ये 0.004 है० इस प्रकार कुल 0.166 है०, श्रेणी-5(3)ड कृषि योग्य बंजर भूमि को शासनादेश संख्या-258/16(1)/73-राजस्व-1, दिनांक-09.05.1984 एवं यथासंशोधित शासनादेश संख्या-1695/97-1-1 (60)/93-280-रा०-1, दिनांक-12.09.1997 में निहित प्राविधानों के अधीन राज्य सरकार की संस्थाओं/वाणिज्यिक विभागों/निगमों को वर्तमान प्रचलित बाजार मूल्य की दर से निकाले गये नजराने तथा मालगुजारी के 150 गुने के बराबर की धनराशि एकमुश्त वसूल कर निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन पट्टे पर उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० (यू०पी०सी०एल०) को सशुल्क आवंटित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1. प्रश्नगत जेड०ए० भूमि आवंटन के पूर्व जमींदारी विनाश एवं भू-सुधार अधिनियम की धारा-132 एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
2. चूंकि जिलाधिकारी द्वारा संबंधित शासनादेश दि०-9.5.1984 के अधीन निर्धारित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्राविधानों का अनुपालन अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।
3. प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की गयी है। इस संबंध में आवासीय प्रयोजन के उपयोग के लिए सम्बन्धित प्राधिकारी व सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जाना जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार पट्टेदार को नहीं होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
5. प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-150/1/85(24)-रा-6 दिनांक-09 अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षों के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30-30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढ़ाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1-1/2 गुना से कम नहीं होगा।

6. प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को नहीं रह जायेगी तो भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।
7. यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।
8. इस संबंध में सिविल अपील संख्या-1132/2011 (एस0एल0पी0)/(सी) संख्या-3109/ 2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य तथा सिविल अपील सं0-436/2011/SLP(C) NO. 20203/2007 झारखण्ड राज्य व अन्य बनाम पाकुर जागरण मंच व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश दि0-जनवरी, 2011 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी। जिलाधिकारी इसे सुनिश्चित करेंगे।
10. भू-उपयोगिता व पट्टे में इंगित शर्तों के अनुपालन के सन्दर्भ में शासन/जिलाधिकारी/अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकता है।
11. आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों बिन्दु संख्या-01 से 10 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

कृपया इस संबंध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश एवं इस शासनादेश की शर्तों की अनुपालन स्थिति से भी अनिवार्य रूप से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(जे0पी0 जोशी)
अपर सचिव।

पू0प0सं0- 208 / XVIII(II) / 2015-03(34) / 2015 तददिनांकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, ऊर्जा भवन, कांवली रोड, देहरादून।
5. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड सचिवालय।
6. प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार सिंह)
अनुसचिव।